हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 21 अगस्त 2024, समय 1305 (5 मिनट)

उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर हाल ही के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा भारत बंद के आह्वान को हरियाणा और चंडीगढ़ में समर्थन नहीं मिला।हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार, जींद, रेवाड़ी, अंबाला, सिरसा, रोहतक, कठुआ, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल कैथल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत बंद का कोई असर नहीं देखा गया। बाज़ार खुले हैं और सभी प्रकार के वाहन सड़कों पर आम दिनों की तरह चल रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय, बैंक और पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। चिकित्सा देखभाल, पेयजल, सार्वजनिक परिवहन एवं रेल सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। राज्य सरकार ने भारत बंद के आह्वान के मद्देनज़र कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है।

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने आज हरियाणा में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और पार्टी के अन्य नेता उनके साथ मौजूद रहे ।भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी को कल राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था ।नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह ने श्रीमती किरण चौधरी को सफलता के लिए शुभकामनायें दींऔर कहा कि,भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक किरण चौधरी के साथ हैं और उनके अलावा जोगी राम सिहाग,राम कुमार गौतम,रामनिवास सुरजाखेड़ा,अनूप धानक नयनपाल रावत और गोपाल कांडा सहित कई विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया है ।उल्लेखनीय है कि ,दो माह पहले श्रीमती किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गयी थीं।

जम्मू के उधमपुर जिले में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की गश्त के दौरान हुए आंतकी हमले में शहीद हुए बल के निरीक्षक कुलदीप मलिक का अंतिम संस्कार आज जींद में उनके पैतृक गांव निडानी में राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया ।कई वरिष्ठ अधिकारीयों और स्थानीय नेताओं व व आम लोगो न उन्हें अंतिम श्रदांजलि दी शहीद कुलदीप मालिक का एक बेटा सेना में और दूसरा बेटा RPF में सेवारत है ।शहीद कुलदीप काम शव आज ही उनके पैतृक गांव लाया गया था।

गुरुग्राम के मानेसर में रक्षा अधिकारियों के लिए अपनी तरह का पहला प्रमाणन कार्यक्रम कल से शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान द्वारा रक्षा मंत्रालय के तहत महानिदेशालय पुनर्वास के साथ मिलकर आयोजित किया गया है।दो सप्ताह के प्रमाणन कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के 30 वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का समापन इस महीने की 31 तारीख को होगा। कार्यक्रम में एयर वाइस मार्शल, मेजर जनरल और रियर एडमिरल सहित अन्य अधिकारियों ने भागीदारी की। प्रतिभागियों ने कॉर्पोरेट प्रशासन और इसकी बारीकियों को समझने की इच्छा और उत्साह व्यक्त किया।कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को स्वतंत्र निदेशक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराना और उन्हें प्रभावी ढंग से योगदान करने में मदद करना है।

कुश्ती में, भारत के रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको-रोमन 110 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता।रौनक ने कांस्य पदक मुकाबले में तुर्किये के एमुरुल्लाह कैपकन को 6-1 से हराया। इससे पहले, रौनक हंगरी के ज़ोल्टन कज़ाको से सेमीफाइनल मुकाबला 0-2 से हार गए थे।

संघ लोक सेवा आयोग-यूपीएससी ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से निर्देश मिलने के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधी भर्ती संबंधी विज्ञापन रद्द कर दिया है।इससे पहले कल सरकार ने आयोग से इस विज्ञापन को

रद्द करने को कहा था। कुछ दिन पहले यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया था।कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष प्रीती सूदन को पत्र लिखकर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों, विशेषरूप से आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए आरक्षण सरकारी नौकरियों में सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की वचनबद्धता का आधार है। इसका लक्ष्य ऐतिहासिक न्याय सुनिश्चित करना और समावेशिता को बढावा देना है। डॉ. सिंह ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है सामाजिक न्याय के प्रति संविधान के इस आदेश का पालन किया जाए कि सरकारी सेवाओं में वंचित समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री से भरे जाने वाले पद विशेषज्ञता और एकल संवर्ग वाले समझे जाते हैं, इसलिए उनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस पहलू की समीक्षा की जाए।